

महालेखाकार (लेखापरीक्षा II), केरल का कार्यालय
Office of the Accountant General (Audit II), Kerala

प्रेस ब्रीफ
Press Brief

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली - केरल (2025 की रिपोर्ट संख्या 4) पर निष्पादन लेखापरीक्षा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट, केरल सरकार को 9 अक्टूबर 2025 को विधान सभा में रखा गया था। रिपोर्ट में उजागर किए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं का सारांश नीचे दिया गया है:

The Report of the Comptroller and Auditor General of India on Performance Audit on Integrated Financial Management System – Kerala (Report No. 4 of 2025) for the year ended 31 March 2023, Government of Kerala was placed in the Legislative Assembly on **9th October 2025**. The summary of the important points highlighted in the Report is given below:

- सेवा स्तर समझौते के अभाव के कारण, सरकार परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक मजबूत आधार प्रदान नहीं कर सकी। परिवर्तन अनुरोधों की स्थिति और की गई कार्रवाइयों से संबंधित दस्तावेज़ अनुपलब्ध रहे, जिससे प्रणाली समाकलक पर निर्भरता बनी रही।
Due to absence of a Service Level Agreement, government could not provide a strong foundation for the implementation of the project. Documentation regarding the status of change requests and actions taken remained unavailable, leading to dependence on the System Integrator.
- कल्पित सॉफ्टवेयर विकास जीवन चक्र मॉडल के विपरीत, मॉड्यूल को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा आठ वर्षों की अवधि में टुकड़ों में विकसित किया गया। आईएफएमएस-के समीक्षा बैठकों के दौरान लिए गए निर्णय पर आगे के विकास के लिए एकमात्र कार्रवाई बिंदुओं के रूप में भरोसा किया गया।
Contrary to the envisaged Software Development Life Cycle model, the modules continued to be developed in a piecemeal manner by National Informatics Centre (NIC) extending over a period of eight years. The decision taken during the IFMS-K review meetings were relied upon as the sole action points for further development.
- लेखापरीक्षा में पाया गया कि नियोजित डेटा प्रवासन उपकरणों और लॉग विश्लेषण के संबंध में विवरण विभाग के पास उपलब्ध नहीं थे। डेटा प्रवासन के दौरान उत्पन्न प्रवासन की पूर्णता की पुष्टि करने वाली हस्ताक्षरित पूर्व-प्रवासन और प्रवासन के बाद की रिपोर्ट, अपवाद रिपोर्ट (त्रुटियाँ / अखंडता त्रुटि रिपोर्ट) और कोषागारों द्वारा प्राप्त इसके सुधार और पुष्टि भी उपलब्ध नहीं थी।
- Audit found that the details in respect of data migration tools employed and log analysis were not available with the department. Signed pre-migration and

post-migration reports confirming the completeness of migration, exception reports (errors/ integrity error reports) generated during data migration and its rectification and confirmation obtained by treasuries were also not available.

- स्वीकृति परीक्षण योजना तैयार नहीं की गई थी और विकास और उत्पादन वातावरण से अलग कोई सुरक्षित परीक्षण वातावरण नहीं था। अंतिम स्वीकृति परीक्षण के लिए किसी तीसरे पक्ष की पेशेवर परीक्षण एजेंसी को नहीं सौंपा गया था।

Acceptance Test Plan was not prepared and there was no secure test environment segregated from the development and production environments. No third-party professional testing agency was entrusted with the Final Acceptance Testing.

- अनुमोदित कार्यात्मक आवश्यकता विनिर्देश में निर्दिष्ट 251 आवश्यकताओं में से, 100 आवश्यकताओं को विकसित नहीं किया गया था।

Out of the 251 requirements specified in the approved Functional Requirements Specification, 100 requirements were not developed.

- पुनर्निर्मित व्यावसायिक प्रक्रियाओं के साथ संरेखित करने के लिए केरल कोष कोड/केरल वित्तीय कोड और बजट मैनुअल में संशोधन नहीं किया गया था।

Kerala Treasury Code/ Kerala Financial Code and budget manuals were not amended to align with re-engineered business processes.

- बजट 2.0 आवेदन में विनियोजन की अन्य इकाइयों में बचत तक अतिरिक्त प्राधिकरण को प्रतिबंधित करने के लिए सत्यापन नियंत्रण का अभाव था। व्यय के आंकड़ों में मले. (ले व ह) द्वारा बाद में किए गए संशोधन बजट 2.0 आवेदन में प्रतिबिंबित नहीं हुए।

The Budget 2.0 application lacked validation control to restrict the additional authorisation up to the savings in other units of appropriation. The modification subsequently made by AG (A&E) in the expenditure figures were not reflected in Budget 2.0 application.

- वित्तीय वर्ष के समापन के बाद विनियोजन की एक इकाई से दूसरी इकाई में अतिरिक्त / बचत के पुनः विनियोजन, या नियंत्रण / संवितरण अधिकारियों द्वारा आत्मसमर्पित धन की बहाली को रोकने के लिए प्रणाली में सत्यापन नियंत्रण की कमी थी। अनुदान के भीतर संभावित बचत का विश्लेषण करने और अतिरिक्त प्राधिकरण को नियमित करने के लिए आवश्यक अनुदान के लिए पूरक मांगों की गणना करने के लिए प्रणाली में कोई प्रावधान नहीं है।

The system lacked validation control to prevent re-appropriation of excess/ savings from one unit of appropriation to another, or resumption of funds surrendered by the Controlling/ Disbursing officers after the close of the financial year. There is no provision in the system to analyse probable savings within the grant and to calculate supplementary demands for Grant required for regularising the additional authorisation.

- एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी खाते में धन के विलंबित क्रेडिट के लिए दंडात्मक ब्याज की स्वतः गणना की कार्यक्षमता विकसित नहीं की गई है। चालानों का समय पर विमोचन नहीं किया जाता है और रिफंड आवेदनों के प्रसंस्करण के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

The functionality of auto calculation of penal interest for delayed credit of money to government account by agency banks has not been developed. Timely defacement of challans is not done and no time limits are set for processing refund applications.

- व्यय मापांक में कमियां थीं, जैसे कि प्रणाली के भीतर मंजूरी आदेशों या कार्यवाही का अभाव, जिसके कारण कोष को भुगतान के प्रसंस्करण के लिए बिलों की भौतिक प्रतियों पर निर्भर रहना पड़ा। एचआर आवेदन - स्पार्क में असंगत और अमान्य डेटा था जिसने प्रणाली के उद्देश्य को विफल कर दिया।

Expenditure module had deficiencies, such as the absence of sanction orders or proceedings within the system due to which the Treasury had to rely on physical copies of the bills for processing payments. The HR application - SPARK contained inconsistent and invalid data which defeated the objective of the system.

- लेखों और लेखापरीक्षा मापांक में, डेटाबेस तक गैर-पेशेवर बैकएंड पहुंच के कारण एक जोखिम मौजूद था, जिससे संग्रहीत प्रक्रियाओं को 'दिनांक' चर को मैन्युअल रूप से संपादित करके निष्पादित किया जा सकता था। सिस्टम जीएसटी लेनदेन का मिलान करने में सक्षम नहीं है जिसके परिणामस्वरूप जीएसटी की असमाहित राशि हुई।

In the Accounts and Audit module, there existed a risk due to unprofessional backend access to the database, which allowed stored procedures to be executed by manually editing 'date' variables. The system is not capable of reconciling GST transactions which resulted in unreconciled amount of GST.

- कोर ट्रेजरी सेविंग्स बैंक मापांक में कमियां थीं, जैसे कि टीआईएस से टीएसबी में खातों का गैर-प्रवास और निष्क्रिय पीडी खातों को बंद करने के लिए सिस्टम नियंत्रण की कमी। टीएसबी में रखे गए 3,136 खातों में नकारात्मक शेष राशि देखी गई। खातों के लिए केवाईसी विवरणों को कैप्चर न करना, हस्ताक्षर सत्यापन में समस्याओं ने अनजाने में होने वाली त्रुटियों की संभावना और इन खातों के संचालन के दौरान कदाचार की संभावना को बढ़ा दिया।

Core Treasury Savings Bank module had deficiencies, such as the nonmigration of accounts from TIS to TSB and the lack of system controls for closing inoperative PD accounts. Negative balances were noticed in 3,136 accounts maintained in TSB. Non-capturing of KYC details for accounts, issues in signature verification increased the likelihood of unintentional errors and possibility of malpractices during the operation of these accounts.

- सिस्टम ने विभिन्न वेब-आधारित अनुप्रयोगों में कई लॉग इन की अनुमति दी। राज्य बजट आवेदन डीबी2 के बिना लाइसेंस वाले संस्करण पर काम कर रहा था। कोई डेटाबेस प्रबंधक

उपलब्ध नहीं था और बिजनेस निरंतरता / आपदा प्रबंधन योजना भी तैयार नहीं की गई थी ।

The system permitted multiple logins across various web-based applications. The state budget application was operating on an unlicensed version of DB2. No Database Administrator was available and the Business Continuity/ Disaster Management Plan was also not devised.